भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 920

(जिसका उत्तर सोमवार, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 (शक) को दिया गया)

मॉरीशस प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीएम) के साथ समझौता ज्ञापन

920. श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री भोला सिंहः
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
डॉ. सुकान्त मजूमदारः
श्री राजा अमरेश्वर नाईकः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में सहयोग को बढ़ावा देने और इसे सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और मॉरीशस के प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीएम) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सूचना के आदान-प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और क्षमता संवर्धन की पहल के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के मामलों में सहयोग को बढ़ावा देने और इसे सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख): जी, हां। सरकार ने दिनांक 22 दिसंबर, 2021 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग तथा कंपीटीशन कमीशन ऑफ मॉरीशस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ग): सरकार ने पूर्व में सीसीआई द्वारा अपने समकक्षों के साथ निम्नलिखित आठ समझौता ज्ञापनों को अनुमोदित कर दिया था जो सेमिनारों, कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षणों के माध्यम से सीमा-पार प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने तथा तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धा कानून एवं नीति, प्रवर्तन सहयोग की बेहतर समझ बनाने हेतु प्रतिस्पर्धा कानून विकास एवं प्रवर्तन में अनुभव की साझेदारी हेतु निष्पादित किए गए थे :-

(i) फेडरल एंटी-मोनोपोली सर्विस, रूस (ii) यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल ट्रेड कमीशन, यूनाइटेड स्टेट्स (iii) द ऑस्ट्रेलियन कम्पीटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन, ऑस्ट्रेलिया (iv) डायरेक्टर जनरल फॉर कम्पीटिशन ऑफ द यूरोपियन कमीशन, यूरोपीय संघ (v) कम्पीटीशन ब्यूरो, कनाडा, (vi) ब्रिक्स कम्पीटिशन अथॉरिटीज, ब्रिक्स देश (vii) एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल फॉर इकॉनोमिक डिफेंस ऑफ ब्राजील, ब्राजील और (viii) जापान फेयर ट्रेड कमीशन, जापान।

*****